



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2809]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 2, 2017/आश्विन 10, 1939

No. 2809]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 2, 2017/ASVINA 10, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 2017

**का.आ. 3210(अ).**—संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण की व्यवहार्यता की जांच करने की दृष्टि से अन्य पिछड़ा वर्गों के एक आयोग का निम्नानुसार गठन करते हैं :—

- (i) अध्यक्ष - जस्टिस (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय दिल्ली
  - (ii) सदस्य - डॉ. जे.के. बजाज, निदेशक, समाजनीति समीक्षण केंद्र, नई दिल्ली
  - (iii) सदस्य (पदेन) - निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता
  - (iv) सदस्य (पदेन) - महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत
2. आयोग के प्रस्तावित विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
- (i) केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्गों की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना।
  - (ii) ऐसे, पिछड़े वर्गों के अंतर्गत उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड, मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना, तथा
  - (iii) अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ करना।
3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।
4. आयोग हेतु कार्यालय व्यवस्था एवं सचिवालयीय सहायता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
5. आयोग के अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि में आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

6. आयोग के सचिव को सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कनिष्ठ अधिकारी नहीं होगा।

रामनाथ कोविंद  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 12015/09/2017-बी.सी.-II]

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**(Department of Social Justice and Empowerment)**

**ORDER**

New Delhi, the 2nd October, 2017

**S.O. 3210(E).**—In exercise of the powers conferred by article 340 of the Constitution the President is pleased to appoint a Commission for Other Backward Classes to examine sub-categorisation of Other Backward Classes with the following composition namely:—

- |       |                     |   |  |
|-------|---------------------|---|--|
| (i)   | Chairperson         | - | Justice (Retd.) G. Rohini, Chief Justice (Retd.), Delhi High Court |
| (ii)  | Member              | - | Dr. J.K. Bajaj, Director, Centre for Policy Studies, New Delhi     |
| (iii) | Member (Ex-officio) | - | Director, Anthropological Survey of India, Kolkata                 |
| (iv)  | Member (Ex-officio) | - | Registrar General and Census Commissioner, India                   |
2. The terms of reference of the Commission are as under:—
- |       |  |
|-------|--|
| (i)   | to examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the castes or communities included in the broad category of Other Backward Classes with reference to such classes included in the Central List; |
| (ii)  | to work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for sub-categorisation within such Other Backward Classes; and  |
| (iii) | to take up the exercise of identifying the respective castes or communities or sub-castes or synonyms in the Central List of Other Backward Classes and classifying them into their respective sub-categories.                     |
3. The Headquarters of the Commission shall be situated at New Delhi.
4. The Secretarial assistance and office space for the Commission shall be provided by the Ministry of Social Justice and Empowerment.
5. The Commission is required to present their Report to the President within a period of twelve weeks of assumption of charge by the Chairperson of the Commission.
6. The Secretary of the Commission shall be appointed by the Government and he/she shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

RAM NATH KOVIND  
PRESIDENT

[F. No. 12015/09/2017-BC-II]

B. L. MEENA, Jt. Secy.